POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2026/अंक 03

मासिक प्रेषण दि. 8 मार्च, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

बजट

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 मार्च, 2026 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

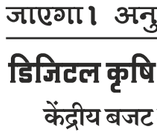

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट प्रस्तुत किया गया। बजट विकसित भारत के निर्माण, चहुंमुखी समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ते कदमों का पथ दिग्दर्शन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करेगा।

बजट में खेती और अन्नदाता को खास अहमियत दी गई है। वित्त मंत्री ने बहुभाषी एआई टूल 'भारत विस्तार' के जरिए डिजिटल कृषि क्रांति की नींव रखकर, उत्पादकता दोगुनी करने, जोखिम घटाने और किसानों की आय बढ़ाने का रोडमैप पेश किया है। साथ ही, ग्रामीण स्तर तक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया है।

बजट में युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा स्किल डवलपमेंट को एक साझा रणनीति से जोड़कर, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अनुसंधानों पर विशेष जोर रहेगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने जैसी कई घोषणाएं बजट में शामिल की गई है।

वहीं राज्य विधानसभा में भी वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया। उन्होंने प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बजट में अच्छे प्रावधान रखे हैं। वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगों को बढ़ावा देने और साथ ही बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास पर खास नजर रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर, विकसित राजस्थान का संकल्प व्यक्त किया है।

मानना है, भारत के हर गांव व हर राज्य पूर्ण विकसित होंगे तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। प्रदेश में डबल इंजन सरकार होने से जनता भी उत्साहित है और उसे भरोसा है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोई कसर नहीं रहने देंगे।

बजट घोषणाओं को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आवश्यक है। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

डिजिटल कृषि क्रांति की रखी नींव

केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले बजट से 7% ज्यादा है। वित्त मंत्री द्वारा 'भारत विस्तार' नाम से एआइ कृषि प्लेटफार्म शुरू करने की घोषणा की गई है। इससे कृषि में डिजिटल क्रांति के जरिए किसानों को खेती से संबंधित सभी जानकारियां एवं सुविधाएं मिल सकेंगी। किसान जागरूक होंगे और खेती में नवाचार आएंगे। बजट में किसान की उत्पादकता बढ़ाने एवं उसे अपनी फसल का सही लाभ दिलाने के प्रयास किए गए हैं।

किसान होंगे तकनीकों से सशक्त व समृद्ध

राजस्थान के बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने खेती और किसानों के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। बजट में प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए अनुदान व ऋण सुविधाओं में इजाफा करने के साथ ही उत्पादकता बढ़ाने, कृषि को नई तकनीकों से जोड़ने, सिंचाई, बीज, बिजली, कृषि यंत्रीकरण, भंडारण और प्रोसेसिंग के साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणाएं कर, खेती और किसानों को सशक्त व समृद्ध बनाने के लिए सार्थक कदम बढ़ाए हैं। माना जा रहा है इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026

जैसा कि विदित है 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' प्रति वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष का विषय 'सुरक्षित उत्पाद, आत्म विश्वासी उपभोक्ता' रखा गया है।

आज उत्पादों की सुरक्षा गंभीर चिंता का मुद्दा बन गया है, जो उपभोक्ताओं के विश्वास, जीवन, स्वास्थ्य और विकास को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। कई बैन किए गए उत्पाद ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन खराब उत्पादों से बचाने के लिए पर्याप्त कानूनी ढांचा नहीं है। यह प्रदूषण और कीमती संसाधनों की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। उपभोक्ता संस्थाएं इस अवसर पर उक्त विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जनसाधारण को जागृत और सचेत करें। कृपया कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ग्राम गदर' को अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2025

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 44 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ट पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2025 का विषय जिस पर उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही है, वह है:

'वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है'

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2025 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2026 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 (राजस्थान), फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395

ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org

भारत मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब

केंदीय बजट में पहली बार स्वास्थ्य का बजट 1 लाख 4 हजार 500 करोड़ को पार कर गया है। देश में आयुर्वेद के 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों में 24 घंटे चलने वाले इमरजेंसी और ट्रोमा केयर सेंटर बनेंगे। पांच रीजनल मेडिकल हब तैयार होंगे। मेडिकल शिक्षा में इलाज व रिसर्च एक साथ होगी। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के साथ आधुनिक जांच व पुनर्वास की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अगले 5 साल में 1.5 लाख केयरगिवर्स को ट्रेंड किया जाएगा। वे लंबे समय तक बुजुर्गों की देखभाल व स्वास्थ्य जरूरतें पूरी करेंगे। माना जा रहा है कि इससे भारत मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब बनेगा।

स्वास्थ्य एवं उपचार को खास अहमियत

राजस्थान के बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। उदयपुर को मेडिकल हब बनाने, गंभीर मरीजों व सड़क हादसों के मामलों में त्वरित इलाज, मानसिक स्वास्थ्य के उपचार की व्यवस्था, 'मां' फंड में इजाफा करने, निःशुल्क जांच और दवाइयों के लिए 3500 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करने एवं जन स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं में बजट प्रावधान बढ़ाकर कई सुविधाएं देने की घोषणाएं की गई हैं। बजट में 32 हजार 526 करोड़ रुपए की राशि अस्पतालों के विस्तार, नए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आइपीडी सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में लगाई जाएगी। ट्रोमा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 150 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

शिक्षा क्षेत्र बनेगा रोजगारोन्मुखी

केंद्र सरकार के बजट में शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के 800 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की पढ़ाई और सुरक्षा को मजबूती दी जाएगी। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेंगे, जो इंडस्ट्री, शिक्षा, रिसर्च के इंटीग्रेटेड हब होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए बजट में और भी कई घोषणाएं की गई हैं।

शिक्षा को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा

राजस्थान के बजट में शिक्षा को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के जरिए एक लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इससे शिक्षा के साथ युवा रोजगार देने वाले बनेंगे। मेधावी छात्रों को टैबलेट/लेपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपए का ई-वाउचर दिया जाएगा। स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। तीस करोड़ रुपए की लागत से नवीन टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। कॉलेज छात्रों के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाने, 11 नए महाविद्यालय और 2 कृषि महाविद्यालय खोले जाने के साथ ही उच्च शिक्षा में अनुसंधानों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर

राजस्थान के बजट में महिलाओं के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना में विस्तार कर महिलाओं को कम ब्याज दर पर 1.50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकेगा। स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को भी कम ब्याज दर पर एक करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा मिलेगी। महिला मित्र योजना के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक महिला मित्र नियुक्त की जाएगी। महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट बनवाए जाएंगे। शिक्षा और आवासीय सुविधाओं के लिए भी बजट में कई प्रावधान कर महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

महिला उद्यमिता को दिया प्रोत्साहन

केंद्रीय बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने जैसे कई प्रावधान हैं। महिला उद्यमियों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए से 'शीमार्ट प्लेटफॉर्म' स्थापित होगा। स्टार्टअप व एमएसएमई क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को कई सुविधाएं मिलेंगी। 'लखपति दीदी' योजना का दायरा बढ़ेगा।

बुनियादी ढांचे को दी बड़ी प्राथमिकता

केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 12.21 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। जो पिछले साल की तुलना में लगभग 9% अधिक है। जिसमें सड़क रेलवे और ऊर्जा एवं जल प्रदाय परियोजनाओं पर खास ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में 7 नए हाई-स्पीड रेलवे कॉरीडोर बनाने की घोषणा की गई है। पर्यावरण व ऊर्जा के लिए केंद्रीय बजट में 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान

राजस्थान के बजट में विकास को तेज गति दिए जाने के लिए वित्त मंत्री का ध्यान सड़क, जल आपूर्ति, ऊर्जा, ग्रामीण व शहरी विकास, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर रहा है। इसके लिए बजट में बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय कर नई-नई योजनाओं की घोषणाएं की गई है। इससे शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण औद्योगिक विकास को भी तेजी से बल मिलेगा।

बजट में अन्य राहतभरी खास घोषणाएं

- केंद्रीय बजट में एमएसएमई और उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ग्रोथ फंड का प्रावधान किया गया है। जिसमें छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। आर्थिक सवृद्धि हेतु एक रणनीतिक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। जिसके अंतर्गत विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ग्रामीण स्तर तक कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), निवेश, निर्यात और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।

- राजस्थान के बजट में 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने, फसल का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मिशन राजगिफ्ट और पशुपालकों को उत्पाद तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है।
- राजस्थान में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत शहरों के आसपास के 6,245 गांवों को शामिल किया गया है। इस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर जल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष में 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।

'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक

फार्म-4 (नियम 8)

'ग्राम गदर हिन्दी मासिक' के स्वामित्व का विवरण और अन्य विशिष्टियाँ जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अन्तिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-

1.	प्रकाशन का स्थान	–	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	–	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	–	भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर
	नागरिकता	–	भारतीय
	क्या विदेशी है	–	नहीं
4.	प्रकाशक का नाम	–	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	–	भारतीय
	क्या विदेशी है	–	नहीं
	पता	–	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
5.	सम्पादक का नाम	–	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	–	भारतीय
	क्या विदेशी है	–	नहीं
	पता	–	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	–	एक मात्र स्वामी प्रदीप सिंह महता

मैं प्रदीप सिंह महता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

प्रदीप सिंह महता

प्रकाशक के हस्ताक्षर

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स', जयपुर